

'मंत्री धारीवाल ने 45 करोड़ रू. की बेशकीमती जमीन कोटा निवासी अपने चहेते को 6 करोड़ रू. में आवंटित की थी'

राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के इन आरोपों के बाद अब आर.जी. मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी को आवंटित 2377 वर्गमीटर भूमि का आवंटन रद्द करने की तैयारी शुरू हो गई है

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर, 26 जून। राजधानी जयपुर के प्रताप नगर की हाई प्रोफाइल स्क्रीम 'राज आंगन' में आर.जी. मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी को दी गई 23277.36 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन रद्द करने की तैयारी शुरू हो गई है।

इस संस्था ने कौशल विकास संस्थान बनाने के नाम पर 12 जून 2020 को राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड से यह बेशकीमती भूमि आवंटित करवाई थी, लेकिन इस पर अब प्ले स्कूल बनाने की तैयारी थी, इसके लिए बाकायदा नक्शे तक पेश कर दिए गए थे। जबकि, आवंटन के समय हाऊसिंग बोर्ड ने शर्त रखी थी कि 2 वर्ष के भीतर इस भूमि पर कौशल विकास संस्थान का निर्माण

■ मजेदार बात यह भी है कि, राजधानी जयपुर के प्रताप नगर की पॉश स्क्रीम "राज आंगन" में कौशल विकास संस्थान बनाने के नाम पर जून 2020 में यह जमीन आवंटित की गई थी, परन्तु संस्था ने इस भूमि पर प्ले स्कूल बनाने के नक्शे पेश किए हैं।

■ मामला उजागर होने के बाद मंत्री धारीवाल के निर्देश पर सोमवार को आवासन मंडल के अधिकारियों ने इस एजुकेशन सोसायटी के प्रतिनिधियों की व्यक्तिगत सुनवाई की, अब भूमि आवंटन निरस्त करने का फैसला प्रमुख शासन सचिव के स्तर पर होगा।

पूर्ण कर लिया जाये, लेकिन आज तक ऐसा कोई निर्माण मॉकै पर नहीं हुआ। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने भी इस आवंटन पर सवाल उठाते हुए मंत्री शांति

वर्गमीटर भूमि मात्र 6 करोड़ 18 लाख रुपये में आवंटित करवाई है। प्रताप नगर की राज आंगन सोसायटी में जहां यह जमीन आवंटित की गई है, वहां कौशल विकास जैसा कोई काम नहीं होता। सांसद किरोड़ीलाल मीणा के इन आरोपों के बाद हरकत में आये हाऊसिंग बोर्ड प्रशासन ने आनन-फानन में पूरे मामले की जांच करवाई। इसके बाद क्रमशः 9 जून और 19 जून को दो नोटिस आर.जी.मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी के सचिव को थमाए गए। जब अधिकारियों ने हकीकत खंगाली तो मालूम चला कि, इस संस्था ने जो नक्शा आवासन मंडल के समक्ष पेश किया है, वह कौशल विकास संस्था का न होकर किसी प्ले स्कूल जैसा है। इसके बाद संस्था से जवाब मांगा गया।

यू.डी.एच. मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर उप आवासन आयुक्त के.सी.ढाका ने गत 19 जून 2023 के नोटिस में एजुकेशन सोसायटी के सचिव को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 23 जून का समय दिया गया। सोमवार दोपहर 3 बजे इस मामले पर सुनवाई भी हुई, अब जमीन के आवंटन के निरस्तकरण की फाइल नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव के पास पड़ी है, जहां इसके आवंटन को खारिज करने के संबंध में फैसला लिया जायेगा। बताया जा रहा है कि, गत 30 मई 2023 को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस जमीन का आवंटन निरस्त करने के निर्देश दिए थे। भूखंड आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के

अनुसार दो वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य नहीं करने के कारण इस संस्था को आवंटित संस्थानिक भूखंड निरस्त करने का फैसला मंत्री स्तर पर लिया गया, लेकिन आवंटन रद्द करने से पहले एजुकेशन सोसायटी के सचिव को नोटिस देकर जवाब इसलिए मांगा गया, ताकि कोई कानूनी पेचिदगियों का सामना नहीं करना पड़े। आवासन मंडल के अधिकारियों की मानें तो आर.जी.मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी को आवंटित 2377 वर्ग मीटर भूमि संस्थानिक थी, जो कि नियमानुसार संपत्ति आवंटन समिति को बैठक में 20 मार्च 2020 को आवंटित की गई थी, इसके बाद 12 जून 2020 को मंत्री शांति धारीवाल ने भी इसका अनुमोदन कर दिया था।

'एक माह में बंगला खाली करो तथा अब तक का किराया मय ब्याज, पैन्ल्टी अदा करो'

राज्य सरकार ने आई.ए.एस. नीरज के. पवन को अल्टीमेटम दिया

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर, 26 जून। राजधानी जयपुर के प्रताप नगर स्थित राज आंगन योजना (एन.आर.आई. कॉलोनी) में किराये पर रह रहे आई.ए.एस. नीरज के. पवन को एक महीने के अंदर बंगला खाली करना होगा। उन्हें अब तक का किराया भी ब्याज-पैन्ल्टी के साथ राजस्थान आवासन मंडल को चुकाना पड़ेगा।

दरअसल पिछले दिनों राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल ने आई.ए.एस. नीरज के. पवन को किराये पर एन.आर.आई. कॉलोनी में आवास देने का मुद्दा उठाया था। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर राजस्थान आवासन मंडल ने उन्हें नोटिस जारी कर 7 दिनों में जवाब मांगा। आई.ए.एस. नीरज के. पवन द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट जाहिर करते

■ नीरज के. पवन को राज आंगन (एन.आर.आई. कॉलोनी) में सरकार ने पी-21 बंगला किराए पर दिया था, बंगले का स्वामित्व आवासन मंडल के पास है।

■ राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल द्वारा आई.ए.एस. नीरज के. पवन को किराए पर आवास देने का मुद्दा उठाया गया था, उसके बाद नगर विकास मंत्री धारीवाल के निर्देश पर आवासन मंडल ने बंगला खाली करने का आदेश दिया है।

हुए अब उन्हें एक माह के भीतर आवास संस्था पी-21 खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि इस आवास का कब्जा आवासन मंडल को सुपुर्द करने के साथ-साथ अब तक समस्त बकाया किराया मय ब्याज और पेन्ल्टी जमा करवाएं।

चीन ने भी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
समझते थे कि हमारा क्या-क्या दौब पर लग गया है तथा हम हार के कितने नजदीक पहुँच गये हैं, उन लोगों की बात कभी नहीं समझ पायेंगे, जो वागनर/इस्ट का जवाब-जवाब कर रहे थे और इस प्रकार से खुशी मना रहे थे, मानो किसी ने हुकुमत को चुनौती दे दी हो।

चीन सरकार के अखबार "द ग्लोबल टाइम्स" द्वारा प्रकाशित एक ऑपिनियन पीस में इस अखबार के पूर्व कम्प्यूटिस्ट पार्टी सेक्रेटरी तथा इसके लेखक हू शीजिन ने वागनर लड़ाकों के हटने से पहले भविष्यवाणी की थी कि इस बगावत का रूस की स्थिरता पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा तथा प्रिगोजन का बहुत "दुखद" अन्त होगा।

लेखक ने यह भी दावा किया था कि स्थिति "इस दिशा की तरफ बढ़ रही है कि पश्चिम तथा यूक्रेन दोनों ही यह तर्क देना चाहेंगे कि यूक्रेन रूसी सेना को नहीं हार सकता, इससे उसे ऐसे प्रयासों पर प्रोत्साहन होगा, जो "रूस में अन्दरूनी अशांति पैदा कर सकें तथा उसे जारी रख सकें।"

इस घटना पर एक अन्य संपादकीय में, सरकार-संचालित चीनी दैनिक ने कहा कि इस बगावत के फलस्वरूप रूस और यूक्रेन के बीच शान्ति-वार्ता के प्रयास शुरू हो जायेंगे।

लेख में आगे कहा गया है, "कोई भी देश, मॉस्को ने नाटक को देखते हुये, शांडाप्रयाज (दूसरों के दुर्भाग्य से प्राप्त आनन्द) के अनुभव का स्वाद बताने की स्थिति में नहीं है।

ऐसा लगता है मानो नदी के एक पार पर खड़े होकर दूरी पर पार लगी आग को सुरक्षापूर्वक देखा जा रहा हो।

चीन यूक्रेन-संकट के राजनैतिक समाधान के लिये सभी पक्षों के साथ काम करने को तैयार है तथा चीन कूटनीतिक समझौतों की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा इस संकट के निर्णायक समझौते के लिये सभी स्थितियों को पैदा करने तथा उन्हें एकत्रित करने के लिये तैयार है।"

खेलते हुये, केजरीवाल विपक्षी दलों की उस पहली गंभीर एवं ईमानदार कोशिश को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 23 जून को पटना में की गई है। वे जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह अल्पकालीन राजनीति भाजपा को हटाने के उस बड़े एवं मुख्य उद्देश्य को ही नुकसान पहुँचायेगी क्योंकि भाजपा तो संघवाद के उन सिद्धांतों को ही नष्ट करने में लगी है, जो अकेले ही दिल्ली जैसे राज्यों के अधिकारों के संरक्षण के लिए पर्याप्त हैं।

एक दिन में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अधिवक्ता के रूप में वे, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट, दोनों में, कई "हाई प्रोफाइल" केसों में उपस्थित हुईं, जिनमें, संसद भवन व लाल किला शूट आउट केस, जैसिका लाल मर्डर केस, नैना साहनी मर्डर केस और नीतीश कटारा मर्डर केस शामिल हैं।

70 करोड़ रू. में बनी ओ.पी.डी. इमारतों की छतें टपकीं

कोटा, 26 जून (निर्स)। नगर विकास न्यास द्वारा कोटा मेडिकल कॉलेज के जे.के.लोन और एम.बी.एस. अस्पताल परिसर में 70 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई दो नई बिल्डिंगों के छतिया निर्माण कार्यों की जमकर पोल खुल गई है। इन निर्माण कार्यों में एम.बी.एस. अस्पताल की ओ.पी.डी. बिल्डिंग और जे.के. लोन अस्पताल में ओ.पी.डी. -आई.पी.डी. ब्लॉक का निर्माण शामिल है। दोनों ही निर्माण कार्यों का जिम्मा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने नगर विकास न्यास को सौंपा था।

नगर विकास न्यास के कार्य की गुणवत्ता का नमूना दोनों बिल्डिंगों में वर्तमान में देखा जा सकता है। पूरे निर्माण की पोल पानी का रिसाव खोल रहा है। एम.बी.एस. अस्पताल में भी पानी बहकर आ रहा है। जे.के. लोन अस्पताल में फॉल सीलिंग से रिसाव हुआ। जिसके चलते मरीज और उनके तीमारदार और स्टाफ सभी परेशान हो रहे हैं। जे.के. लोन और एम.बी.एस. की दोनों नई बिल्डिंग इस साल ही शुरू की गई है। एम.बी.एस. अस्पताल में मई माह में ही ओ.पी.डी. ब्लॉक को शिफ्ट किया गया है। जबकि जे.के. लोन अस्पताल में जनवरी महीने में ओ.पी.डी. और आई.पी.डी. शिफ्ट हुए हैं। जे.के. लोन अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण बीते साल हो गया

■ छत पर जमा बारिश का पानी रिसकर अस्पताल के अंदर पहुँचा, अस्पताल में ना केवल जगह-जगह पानी भर गया, बल्कि करंट का खतरा भी पैदा हो गया है।

■ ओ.पी.डी. इमारतों का निर्माण कार्य यू.डी.एच. मंत्री शांति धारीवाल के आदेश पर नगर विकास न्यास को सौंपा गया था।

था। जबकि, एम.बी.एस. अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण इस साल ही पूरा हुआ था। ऐसे में निर्माण के पहले साल में ही पानी का रिस जाना बिल्डिंग की निम्न क्वालिटी को दर्शा रहा है। एक मरीज के तीमारदार साजिद का कहना है कि, अस्पताल में छतिया निर्माण कार्य हुआ है। इसी के चलते पानी जगह-जगह जमा हो रहा है और रिसाव भी हो रहा है। इससे करंट का खतरा भी बना हुआ है। वहीं अन्य तीमारदार चेतन वर्मा का कहना है कि ठेकेदार और निर्माण करवाने वाले लोगों की गलती रही है। जे.के. लोन अस्पताल में रिविटर रात को फॉल सीलिंग से ही भारी मात्रा में पानी बहने लगा। यह गलियारों और लिफ्ट में भी आने लगा था। जिसका वहां पर कार्यरत स्टाफ ने वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पानी की वजह से तीसरे फ्लोर पर तीमारदारों के बैठने की जगह

भी नहीं बना पा रही है। रात के समय उन्हें दूसरे फ्लोर पर ही इंतजार करना पड़ा। ड्रेन चौक होने से छत में जमा हो गया था बारिश का पानी:- अधीक्षक डॉ.आशुतोष शर्मा का कहना है कि छत पर बारिश का पानी जमा हो गया था। उसकी निकासी नहीं हो पा रही थी। छत के कुछ ड्रेन भी चौक थे। इसके चलते जमा पानी ड्रेन और लिफ्ट की वायरिंग के बीच की जगह से फॉल सीलिंग में प्रवेश कर गया। जहां से तीसरे फ्लोर का कुछ हिस्सा गिर गया है। छत पर जमा पानी की निकासी कर रहे हैं। हालांकि अब पानी नहीं आ रहा है। सभी ड्रेन की पूरी तरह से सफाई करा रहे हैं। डॉ. शर्मा ने दावा किया है कि वाडें में किसी तरह का पानी नहीं गया। अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक शिव भगवान मीणा का कहना है कि छत भी कई जगह से खुदी हुई है इसको दुरुस्त करवाया जाएगा।

हिमाचल और उत्तराखण्ड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड, 700 से अधिक सड़के बंद हुईं

शिमला/नैनीताल, 26 जून। बारिश के कारण हिमाचल और उत्तराखण्ड, दोनों पहाड़ी राज्यों में स्थिति काफी खराब हो गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से मंडी जिले में पिछले 20 घंटे में लैंडस्लाइड की दूरीय घटना हुई। इसकी वजह से अचानक बाढ़ आ गई।

हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे सहित 380 सड़कें बंद हैं। ऐसे में 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं, जिनमें से कई पर्यटक हैं। वहीं उत्तराखण्ड में भी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बरसात के बाद हाईवे सहित कई सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कें बंद होने की वजह से यूपी, दिल्ली-एनपीसीआर सहित अन्य राज्यों से पर्यटक और तीर्थ यात्री फंस गए हैं।

अगर कांग्रेस सार्वजनिक रूप से केन्द्र के उस अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी, जिसके तहत दिल्ली की नौकरशाही का नियंत्रण केन्द्र ने अपने हाथों में ले लिया है, तो वह संगठित विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेगी।

कांग्रेस अपने पते बड़ी सावधानी से चल रही है तथा वह अध्यादेश के मुद्दे पर आप को समर्थन देने का वादा नहीं कर रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड्गे तथा राहुल गांधी यह कह चुके हैं कि "भाजपा द्वारा लाई गई किसी भी चीज" का समर्थन करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन सच बात यह है कि अगर कांग्रेस ने अध्यादेश के मुद्दे पर आप का समर्थन नहीं किया या राज्यसभा और लोकसभा में इस मुद्दे पर होने वाले मतदान से स्वयं को और लोकसभा में इस मुद्दे पर होने वाले मतदान से स्वयं को अलग रखा तो यह एक राजनैतिक "हारा-किरी" होगी क्योंकि इसे संगठित विपक्ष के मिशन से दूर होना माना जायेगा।

यह चलाकी भरा दिमागी खेल

'मैंने ही सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई'

नई दिल्ली, 26 जून। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने चौकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि उसने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा है कि फिल्म ऐक्टर सलमान खान भी उसके निशाने पर है। मौका मिलने पर जरूर मारेंगे। यह बात उसने एक समाचार चैनल के साथ बातचीत में कही है। गौरतलब है कि गोल्डी बराड़ भारत का मोस्ट वांटेड है और इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ नोटिस जारी की है। इसके साथ ही गोल्डी बराड़ ने यह भी बताया कि उसने मूसेवाला की हत्या आखिर करवाई क्यों थी? आज तक के साथ इंटरव्यू में मूसेवाला ने कहा कि मूसेवाला विगदा हुआ था। उसके पास पैसे बहुत ज्यादा हो गए थे, इसलिए उसे घमंड हो गया था।

वागनर विद्रोह के बाद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सेना में बगावती रुख को आलोचना की। यह सामान्य व्यवहार है क्योंकि चीन रूस और उसके राष्ट्रपति के साथ "असीमित मित्रता" की घोषणा की थी। चीन कदापि भी रूस को कमजोर नहीं देखना चाहेगा। चीन ने सोचा था कि पुतिन एवं रूस अमेरिका और पश्चिम के खिलाफ उसकी लड़ाई में मददगार होगा। पर अब चीन के शी जिनपिंग के लिए पुतिन "खराब बाजों" की तरह है। भले ही पुतिन तख्तापलट की कोशिश से बाल-बाल बच गए हैं लेकिन प्रिगोजन को विश्वासघात के आरोपों और बगावत के दंड से मुक्ति देना दर्शाता है कि पुतिन की ताकत कितनी सीमित हो गई है। कई लोग इंगित करते हैं कि सत्ता पर उनकी पकड़ व नियंत्रण फिलहाल ठीक नहीं है। पुतिन अजेय हैं, इस किंवदंती को दोबारा स्थापित करना

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है

नई दिल्ली, 26 जून। केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का एक बयान सोशल मीडिया और खबरों में काफी चर्चा का विषय बन गया। शेखावत ने कहा कि, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ई.आर.सी.पी.) बना दूंगा, 46 हजार करोड़ दे दूंगा। बस राज बना दो। (मतलब की राजस्थान में भाजपा की सरकार बना दो)

केन्द्रीय मंत्री शेखावत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि, 46 हजार करोड़ रुपये दे दूंगा। राजेंद्र राठौड़ यानी नेता प्रतिपक्ष यहीं है राजेंद्र राठौड़ का राज बना दो।

■ यह वीडियो रिविटर को सवाई माधोपुर के सर्किट हाउस में हुई भाजपा के एक कार्यकर्ता का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि, 46 हजार करोड़ रुपये दे दूंगा। राजेंद्र राठौड़ यानी नेता प्रतिपक्ष यहीं है राठौड़ का राज बना दो।

राज बना दो। दरअसल वायरल वीडियो रिविटर को सवाई माधोपुर में सर्किट हाउस में स्थानीय नेताओं से मुलाकात के वक्त का बताया जा रहा है। जिसमें एक स्थानीय नेता ने केन्द्रीय मंत्री से कहा कि पूर्वी राजस्थान में ई.आर.सी.पी. प्रोजेक्ट की आवश्यकता के बारे में कहते हैं। इस पर केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत यह कहते हुए दिख रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ का राज लानो और 46 हजार करोड़ ले जाओ। वायरल वीडियो में शेखावत कह रहे हैं- ई.आर.सी.पी. बना दूंगा, 46 हजार करोड़ दे दूंगा, राजेंद्र

सिंहजी का राज बना दो। बता दें राजेंद्र सिंह राठौड़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। हालांकि, राष्ट्रपति इस वायरल वीडियो की पूर्णतः पुष्टि नहीं करता है। कांग्रेस ने वायरल वीडियो के जरिये प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़े करते हुए केन्द्रीय मंत्री शेखावत पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने हिम्मत सिंह गुर्जर ने ट्वीट कर कहा संजीवनी घोटाले के आरोपी गजेन्द्र सिंह शेखावत ने ई.आर.सी.पी. का काम रोका है। 13 जिलों की 40 प्रतिशत जनता से धोखा कर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लागू होने से रोकने वाले और इस परियोजना में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने वाला गजेन्द्र

सिंह शेखावत ही है। ठाकर साहब ऐसे बोल रहे हैं जैसे पैसा अपनी जेब से दे देंगे। उल्लेखनीय है कि, राजस्थान में ई.आर.सी.पी. बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर सीएम अशोक गहलोत और केन्द्रीय मंत्री शेखावत के बीच ट्वीटर वार भी हो चुका है। सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अजमेर और जयपुर की जनसभा में ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। लेकिन पीएम मोदी ने वादा पूरा नहीं किया है। राजस्थान से बीजेपी के 24 सांसदों ने कभी पीएम मोदी को अपना वादा याद नहीं दिलाया।

केरल स्टोरी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के लिए तैयार हो जाइए जो आपको निशब्द कर देगी। अपने कैलेण्डर में अप्रैल 2024 को मार्क कर लीजिए। विपुल अमृतलाल शाह, सुदीप्तो सेन, आशीन ए शाह, सनशाइन पिक्चर्स।

निर्माताओं के अनुसार फिल्म एक घटना पर आधारित है। उन्होंने पोस्टर भी जारी किया, जिस पर लिखा है, गुप्त सत्य, जो देश को हिलाकर रख देगा। फिल्म का थ्रौर नहीं दिया जाना नहीं चाहते, जिसके लिये सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं क्योंकि वे भ्रष्टाचार में डूबे हुये हैं।

केजरीवाल ने राजस्थान, जहाँ इस साल के अन्त में चुनाव होने हैं, में अपनी चुनावी सभा में पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुये कहा था, "जब हम यहाँ आ रहे थे, हमने देखा कि गहलोत साहब ने पूरे गंगा नगर तथा इस स्ट्रेडियम के चारों तरफ अन्तःपोस्टर लगवा दिये हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने पिछले पाँच सालों में काम किया होता, तो उन्हें यह इस पर बैन भी लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिबंध लगा पड़ा।

'केजरीवाल जानते हैं, उनकी ग्रोथ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
"आप के मुख्य प्रवक्ता ने आज जो कुछ कहा, वह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने (आप) तो सर्वदलीय मीटिंग वाले दिन भी कांग्रेस के खिलाफ बयान दिये थे।" दिल्ली के कांग्रेस नेता अजय माकन, जिन्हें आप पार्टी सालों से फूटी आँख नहीं सुहा रही है, ने कहा, "मूल बात यह है कि वे (केजरीवाल) जेल जाना नहीं चाहते, जिसके लिये सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं क्योंकि वे भ्रष्टाचार में डूबे हुये हैं।"

केजरीवाल ने राजस्थान, जहाँ इस साल के अन्त में चुनाव होने हैं, में अपनी चुनावी सभा में पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुये कहा था, "जब हम यहाँ आ रहे थे, हमने देखा कि गहलोत साहब ने पूरे गंगा नगर तथा इस स्ट्रेडियम के चारों तरफ अन्तःपोस्टर लगवा दिये हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने पिछले पाँच सालों में काम किया होता, तो उन्हें यह इस पर बैन भी लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिबंध लगा पड़ा।

ही पार्टियाँ (कांग्रेस और भाजपा) भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वसुन्धरा राजे के शासनकाल में, अशोक गहलोत भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे।..... जब अशोक गहलोत की सरकार सत्ता में आई, सचिन पायलट उनसे वसुन्धरा राजे को गिरफ्तार करने के लिये कहते रहे, लेकिन अशोक गहलोत ने कह दिया, "मैं उन्हें गिरफ्तार नहीं करूँगा, वे मेरी बहिन की तरह हैं।"

संगठित विपक्षी मोर्चा के लिये आप और कांग्रेस को साथ-साथ लाना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अपने हाथ में लिया गया एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। दोनों पार्टियों में तभी से अनबन है, जब, करीब एक दशक पहले आप ने कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर दिया था और उसके बाद वह कांग्रेस की कीमत पर फलती-फूलती जा रही है। पिछले वर्ष पंजाब में मिली इकरतफा जीत के बाद, केजरीवाल का फोकस कांग्रेस-शासित राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ पर है। अब, आप ने घोषणा कर दी है कि

अगर कांग्रेस सार्वजनिक रूप से केन्द्र के उस अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी, जिसके तहत दिल्ली की नौकरशाही का नियंत्रण केन्द्र ने अपने हाथों में ले लिया है, तो वह संगठित विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेगी।

कांग्रेस अपने पते बड़ी सावधानी से चल रही है तथा वह अध्यादेश के मुद्दे पर आप को समर्थन देने का वादा नहीं कर रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड्गे तथा राहुल गांधी यह कह चुके हैं कि "भाजपा द्वारा लाई गई किसी भी चीज" का समर्थन करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन सच बात यह है कि अगर कांग्रेस ने अध्यादेश के मुद्दे पर आप का समर्थन नहीं किया या राज्यसभा और लोकसभा में इस मुद्दे पर होने वाले मतदान से स्वयं को और लोकसभा में इस मुद्दे पर होने वाले मतदान से स्वयं को अलग रखा तो यह एक राजनैतिक "हारा-किरी" होगी क्योंकि इसे संगठित विपक्ष के मिशन से दूर होना माना जायेगा।

यह चलाकी भरा दिमागी खेल